



- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड को फल उत्पादन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।
- कृषि विभाग की ओर से फलों एवं मसालों की पौध वितरण का कार्य जारी— किसानों की आय बढ़ाने के लिए की गई नई पहल।
- मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस की ओर से रंगत में हाल में हुई अग्नि दुर्घटना सहित विभिन्न मुद्दों पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया।
- फिट इंडिया अभियान के तहत साइक्लिंग टूर आयोजित कर क्लीन एंड ग्रीन आइलैंड्स का दिया गया संदेश।



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देहरादून में उत्तराखंड के गठन के रजत जयंती समारोह में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 8140 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ वर्षों में खुद को 'स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में स्थापित कर सकता है। देश ने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है, उसका रास्ता वोकल फॉर लोकल से तय होगा। उत्तराखंड इस विजन को हमेशा से जीता आया है। उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिले फलों के उत्पादन में काफी पोटेंशियल रखते हैं। हमें पहाड़ी जिलों को हॉर्टिकल्चर सेंटर बनाने पर फोकस करना चाहिए। ब्लूबेरी, कीवी, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स, ये भविष्य की खेती है। उत्तराखंड अब फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उत्तराखंड लोकप्रिय हो रहा है।



कृषि विभाग की ओर से आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कृषि क्षेत्रों में फलों एवं मसालों की पौध सामग्रियों का वितरण का कार्य शुरु किया गया है। डिगलीपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसानों को वैज्ञानिक खेती के तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह पहल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के तहत की जा रही

है, जिसके अंतर्गत फलों और मसालों के बागवानी विस्तार के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी की सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम में आम, अमरूद, नींबू, अनानास, हल्दी, अदरक और जायफल जैसी फसलों पर विशेष बल दिया जा रहा है। यह प्रयास स्थानीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और जैव विविधता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कल बिडनाबाद ग्राम पंचायत में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 'वंदे मातरम' गायन से हुआ। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट जयंत मुखर्जी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या—निरोध और बाल संरक्षण के अलावा पोक्सो अधिनियम और साइबर अपराध जागरूकता पर डिजिटल सतर्कता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन की राष्ट्रीय महासचिव सरस्वती नारायण ने सामुदायिक विधिक सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे।



मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस की ओर से हाल की में रंगत में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता के. सुगथन ने की। बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने हाल ही में हुई आग दुर्घटना, नशे की बढ़ती समस्या, अवैध शराब, यातायात व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर अपने सुझाव और शिकायतें रखीं। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सभी समस्याओं का हल किया जाएगा।



खेल एवं युवा मामले विभाग तथा शिक्षा विभाग ने सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से कल 'फिट इंडिया मूवमेंट' और 'क्लीन एंड ग्रीन आइलैंड्स' अभियान के तहत साइक्लिंग टूर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की थीम हैशटैग एक्सप्लोर डॉट एक्सपीरिएंस डॉट एंजॉय थी। मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त (सेटलमेंट) तृप्ति कलहंस ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल प्रांगण से साइक्लिंग टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने साइक्लिंग को फिटनेस और सतत विकास का सरल व प्रभावी माध्यम बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और साइक्लिंग प्रेमियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य, पर्यटन और पर्यावरण—जागरूकता का संदेश देना था।



उद्योग निदेशालय की ओर से बर्मानाला ग्राम पंचायत में हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नारियल के खोल, लकड़ी, बेंत एवं बांस उत्पाद निर्माण पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान आर. परमशिवम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने प्रतिभागियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित ऐसे प्रशिक्षण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हैं। उद्योग संवर्धन अधिकारी आर. जनक राव ने विभागीय योजनाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों के विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में 30 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



पर्यटन विभाग ने पर्यावरण एवं वन विभाग और शोल बे ग्राम पंचायत के सहयोग से 'मैंग्रोव वॉक' का आयोजन किया। इस अवसर पर वन रेंजर एल. मोसेस और फॉरेस्टर डी. शेखर ने प्रतिभागियों को मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के जैव-विविधता, पारिस्थितिक महत्व और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया। ग्राम पंचायत शोल बे के प्रधान ए.आर. कुमार ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को इको-गाइडिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर देते हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, पर्यटकों, टूर ऑपरेटर्स, प्रकृतिविदों और पर्यावरण प्रेमियों ने भाग लिया।



पशुपालन विभाग ने विश्व पशु चिकित्सा सेवा, गोवा के सहयोग से पिछले दिनों डॉलीगंज स्थित डॉग स्ट्रलाइजेशन सेंटर में पशु जन्म नियंत्रण एवं सर्जिकल कौशल विकास पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। विभाग की सचिव पल्लवी सरकार ने सात वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी एवं आठ कंपाउंडर्स को प्रमाणपत्र वितरित किए। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ डॉ. क्षितिजा कारगिरवार और डॉ. अमांडा फर्नांडिस ने भी प्रतिभागियों को जानकारी दी।



ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के प्रयास के तहत पशुपालन विभाग ने बाराटांग गांव के 23 किसानों को कुल 400 वनराज चूजे वितरित किए। ये सभी चूजे डॉलीगंज स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म एवं

सेंट्रल हैचरी से उपलब्ध कराए गए। इस पहल का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को बैकयार्ड पोल्ट्री पालन के लिए प्रेरित करना है, जिससे उनकी आजीविका को बढ़ावा मिल सके।

